

मुनीर फिर चले तेहरान...! अमेरिका-ईरान की जंग से पूरी दुनिया परेशान

कि सी शायर का मशहूर शेर है,,,,,
'गर वक़्त मिला तो तेरी
उलझी जुल्फें सुलझा दूँगा,
अभी तो मैं खुद अपनी उलझनों में सुलझाने में लगा हूँ।'
लेकिन, लगता है
पाकिस्तान के फील्ड
मार्शल असीम मुनीर पर
यह शेर लागू नहीं होता।
पाकिस्तान खुद आर्थिक,
राजनीतिक और सामरिक
उलझनों से घिरा है, मगर
मुनीर को अमेरिका और
ईरान की उलझी गुल्थी
सुलझाने की इतनी जल्दी
है कि उनकी अपनी समस्याएं पीछे छूट गई हैं। मुनीर
आज तेहरान पहुंच रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के
मुताबिक उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान-पाकिस्तान
द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना और क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा



प्रसंगवश
राजेश सिरोटिया

‘यदि पाकिस्तान यह मान रहा है कि वह ट्रंप और ईरान के बीच निर्णायक समझौता करा देगा, तो यह उसकी सामरिक क्षमता से कहीं बड़ी उम्मीद है। क्योंकि, पश्चिम एशिया की यह लड़ाई केवल दो देशों के बीच नहीं है। इसमें परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंध, इजराइल, खाड़ी की सुरक्षा, तेल आपूर्ति और वैश्विक व्यापार की पूरी श्रृंखला जुड़ी हुई है। ’

के लिए पाकिस्तान के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। लेकिन इस यात्रा का असली महत्व इससे कहीं बड़ा है। पाकिस्तान लगातार अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है। सवाल है कि क्या वाशिंगटन और तेहरान वास्तव में इस्लामाबाद की मध्यस्थता को निर्णायक महत्व दे रहे हैं? मुश्किल यही है। दोनों देशों के बीच अब केवल युद्ध और युद्धविराम का सवाल नहीं रह गया है। दोनों अपने-अपने नागरिकों और दुनिया के सामने अपनी जीत का नैरेटिव स्थापित करना चाहते हैं। ईरान सम्मान और

समानता के आधार पर समाधान चाहता है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दबाव और प्रतिबंधों की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में मुनीर के लिए दोनों को एक समझौते की मेज पर लाना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ा पेंच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। ट्रंप हॉर्मुज पर अमेरिकी नियंत्रण की बात कर चुके हैं, जबकि ईरान इसे अपने सामरिक हितों का अभिन्न हिस्सा मानता है। दुनिया के तेल और गैस कारोबार के लिए जीवन रेखा बने इस जलमार्ग पर किसी एक शक्ति का दबदबा केवल ईरान-अमेरिका का मामला नहीं रहेगा। भारत,

चीन और दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी इसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा से जोड़कर देखेंगी। यहीं पाकिस्तान की स्थिति सबसे ज्यादा दिलचस्प और विरोधाभासी हो जाती है। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते मजबूत करना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान उसका पड़ोसी है। उधर, सऊदी अरब और तुर्किये के साथ उसका नया पारस्परिक रक्षा समझौता भी है। ऐसे में ईरान समर्थित हूती हमलों और खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के सामने एक साथ कई हितों को साधने की

चुनौती है। तो फिर मुनीर तेहरान क्यों जा रहे हैं? यदि मकसद केवल ईरान-पाकिस्तान संबंधों को मजबूत करना है तो बात समझ में आती है। लेकिन यदि पाकिस्तान यह मान रहा है कि वह ट्रंप और ईरान के बीच निर्णायक समझौता करा देगा, तो यह उसकी सामरिक क्षमता से कहीं बड़ी उम्मीद है। क्योंकि पश्चिम एशिया की यह लड़ाई केवल दो देशों के बीच नहीं है। इसमें परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंध, इजराइल, खाड़ी की सुरक्षा, तेल आपूर्ति और वैश्विक व्यापार की पूरी श्रृंखला जुड़ी हुई है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि मध्यस्थता की घोषणा करना और वास्तव में मध्यस्थ बनने की क्षमता होना दो अलग-अलग बातें हैं। मुनीर शायद तेहरान में मध्यस्थता की तलाश में नहीं, बल्कि पाकिस्तान की घटती सामरिक प्रासंगिकता को बचाने की कोशिश में जा रहे हैं। और यही इस यात्रा का सबसे बड़ा सवाल भी है।... क्या पाकिस्तान दुनिया की उलझी जुल्फें सुलझा पाएगा, जब उसकी अपनी उलझनें अभी बाकी हैं?

न्यूज विंडो

मुंबई में गणपति जुलूस पर अंडे फेंकने पर बवाल, पुलिस तैनात



मुंबई। मझगांव इलाके में गणपति प्रतिमा के आगमन जुलूस के दौरान कथित तौर पर अंडे फेंके जाने के बाद तनाव बढ़ गया। आयोजकों के अनुसार, जुलूस के दौरान पास की इमारतों से अंडे फेंके गए, जिसके बाद दो गुटों में विवाद और नारेबाजी शुरू हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति नियंत्रित की। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा रही है।

गिनी में बारिश के कारण कचरे का पहाड़ धंसा, 30 की मौत



कोनाक्री। गिनी की राजधानी कोनाक्री में भारी बारिश के बाद शहर के सबसे बड़े लैंडफिल में कचरे का पहाड़ धंस गया। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हुई, जबकि छह लोग घायल बताए गए हैं। मलबे में कई घर और झोपड़ियां दब गईं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, लैंडफिल को बंद करने की तैयारी थी और आसपास रहने वालों को जगह खाली करने का नोटिस भी दिया गया था। बारिश से कचरे का वजन बढ़ने के कारण ढेर खिसकने की आशंका है।

न्यूजीलैंड में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन!

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद में बिल लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित कानून में नियम तोड़ने वाले प्लेटफॉर्म पर वैश्विक राजस्व का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। कंपनियों को यूजर्स की उम्र सत्यापित करनी होगी। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का हवाला देते हुए कदम का समर्थन किया है। हालांकि, गठबंधन सहयोगी न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी ने प्रस्ताव पर गंभीर आपत्ति जताई है।

आज का कार्टून



अमरावती में दर्दनाक हादसा... तड़के तीन बजे लगी आग से अफरा-तफरी

महिला अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में धमाका वेंटिलेटर फटने से तीन नवजात की मौत

अमरावती, एजेंसी

महाराष्ट्र के अमरावती में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। यहां जिला महिला अस्पताल के बेबी वार्ड में आग लगने से 3 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, तड़के करीब 3:30 बजे अचानक वेंटिलेटर में विस्फोट होने के बाद आग लगी। आग लगते ही डॉक्टरों, नर्सों और ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों की तत्परता से कई बच्चों की जान बचा ली गई।

वेंटिलेटर फटना असामान्य घटना है। दरअसल उपकरण में हुए शॉर्ट सर्किट की चिंगारी ने स्पलाई हो रही ऑक्सीजन को तुरंत पकड़ लिया। इससे आग इतनी तेजी से भड़की कि उपकरण के अंदर दबाव बनने से वेंटिलेटर में धमाका हो गया। इस भयानक हादसे और धुएं के कारण आईसीयू में भर्ती मरीजों को तुरंत दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा। इस अस्पताल में कुल 39 नवजात बच्चों को रखा गया था। आग लगने के बाद सभी को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। इनमें से 6 बच्चों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी बात यह है कि नवजात शिशु गहन चिकित्सा विभाग करीब एक साल पहले ही शुरू किया गया था। इतने कम समय में आग की घटना सामने आने से अस्पताल की अग्निसुरक्षा और चिकित्सा उपकरणों के रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

NICU में समय से पहले जन्मे, कम वजन वाले और गंभीर स्थिति में भर्ती नवजात बच्चों का इलाज किया जाता है। आग की चपेट में आने से कुछ शिशुओं के हाथ-पैर झूलसने की जानकारी सामने आई है। इन बच्चों को तत्काल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अमरावती के पुलिस कमिश्नर राकेश ओला के मुताबिक वार्ड के तीन कंपार्टमेंट में से एक में 9 नवजात भर्ती थे। आग की चपेट में आने से इनमें से 3 की मौत हो गई, जबकि बाकी 6 को इलाज के लिए दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। इन बच्चों की मौजूदा स्थिति को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

चिकित्सा उपकरणों के रखरखाव पर गंभीर सवाल



चाइल्ड वार्ड में आग के बाद जले उपकरणों का दृश्य।

पांच-पांच की लाख आर्थिक सहायता

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में केयर यूनिट के एक वेंटिलेटर के अंदर धमाके के बाद आग लगने की आशंका है। घटना के सही कारणों की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की हार्दिलेवल जांच के आदेश दिए हैं। फडणवीस ने कहा कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के सचिव को आज ही अमरावती जाकर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मृत नवजातों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रु की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।

दो दिन पहले छिंदवाड़ा में भी हुई घटना

दो दिन पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में भी ऐसी ही घटना हुई थी। शनिवार देर रात करीब 2 बजे वार्मर मशीन के फिलामेंट से निकली चिंगारी के बाद आग लग गई थी। हादसे में 3 नवजात झुलस गए थे। अस्पताल स्टाफ ने फायर फाइटिंग उपकरणों की मदद से आग बुझाई और तीनों बच्चों को प्राथमिक इलाज दिया। इसके बाद तीनों नवजातों को बेहतर इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया था। छिंदवाड़ा में पीडियाट्रिक सर्जन उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे जबलपुर ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इनमें से एक बच्चे का जन्म हादसे से कुछ घंटे पहले ही हुआ था।

न्यूज
ब्रीफ

यूपी-बिहार में बाढ़ का कहर, एमपी में अलर्ट जारी

नई दिल्ली। उत्तर और मध्य भारत में लगातार रह रही बारिश से यूपी-बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश जारी रहने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। यूपी के ललितपुर में बारिश के पानी से सैर नाले पर बना पुल डूब गया और तेज बहाव में बाइक बह गई। वहीं, मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि जबलपुर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई।

मेट्रो एंकर नागपुर के हितेन धारपुरे ने अब बनाया सबसे छोटा इलेक्ट्रो-मैकेनिकल रोबोटिक आर्म

घर की छोटी लैब, बड़े सपने... 17 साल के छात्र ने बनाए दो विश्व रिकॉर्ड

नागपुर, एजेंसी

ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दुनिया बदलने वाले आविष्कार केवल बड़ी-बड़ी लैब और करोड़ों रुपये के उपकरणों से ही बनते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले 17 वर्षीय हितेन धारपुरे ने इस सोच को गलत साबित कर दिया है। घर के एक छोटे से कमरे को अपनी प्रयोगशाला बनाकर उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिला दी। हितेन ने दुनिया का सबसे छोटा इलेक्ट्रो-मैकेनिकल रोबोटिक आर्म तैयार किया है। इस शानदार उपलब्धि के साथ उन्होंने अपना दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। हितेन धारपुरे के इस रोबोटिक आर्म की लंबाई सिर्फ 39.25 मिलीमीटर (करीब 1.54 इंच) है। यह पिछले विश्व रिकॉर्ड से 5 मिलीमीटर से भी ज्यादा छोटा है। आकार में एक पेपर क्लिप से थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन इसकी क्षमता किसी बड़े रोबोट से

कम नहीं है। यह तीन अलग-अलग दिशाओं में घूम सकता है, छोटे-छोटे सामान उठा सकता है और बेहद सटीक तरीके से काम कर सकता है। इतने छोटे आकार में इतनी सटीक तकनीक विकसित करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस रोबोटिक आर्म को तैयार करना बिल्कुल आसान नहीं था। हितेन ने सबसे पहले आधुनिक छ्र

800 से ज्यादा सर्टिफिकेट और सम्मान

यह हितेन का पहला नहीं बल्कि दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले अप्रैल 2025 में उन्होंने दुनिया का सबसे छोटा एआई वेदर स्टेशन बनाकर पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। कम उम्र में ही उन्होंने रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एम्बेडेड सिस्टम्स जैसे क्षेत्रों में 800 से ज्यादा तकनीकी और शैक्षणिक प्रमाणपत्र हासिल किए हैं। उन्हें डेडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जगह मिल चुकी है। हितेन का मानना है कि उनका यह आविष्कार सिर्फ रिकॉर्ड बनाने तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में इसका उपयोग अल्ट्रा-प्रेसिजन माइक्रो सर्जरी, मेडिकल साइंस और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जा सकता है। यानी यह तकनीक आने वाले समय में कई बड़े क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा सकती है।

सॉफ्टवेयर की मदद से इसका पूरा डिजाइन तैयार किया। इसके बाद उन्होंने हार्ड-प्रेसिजन स्रष्टरू3छ प्रिंटिंग तकनीक से इसके बेहद छोटे-छोटे पुर्जे बनाए। रोबोट को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने माइक्रोकंट्रोलर का इस्तेमाल किया। हितेन बताते हैं कि इस रोबोट को बनाने के दौरान उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। कई प्रोटोटाइप

मोटर के दबाव को सह नहीं पाए और उनके छोटे-छोटे हिस्से टूट गए। कई बार रोबोट के अंदर जगह इतनी कम रह गई कि उसके पुर्जे ठीक से काम नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर असफलता से सीखते हुए उन्होंने डिजाइन में छोटे-छोटे बदलाव किए और आखिरकार सफल मॉडल तैयार कर लिया।



कमला नगर थाने से साइकिल से भागा चोर, चकमा देने पहनी हेलमेट
भोपाल। दोपहर मेट्रो

कमला नगर थाने की हवालात से वाहन चोरी का आरोपी अभय राजपूत भाग निकला। घटना शनिवार-रविवार रात 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच की है। वह सीधे घर पहुंचा, कपड़े बदले और सीसीटीवी कैमरों से चेहरा छिपाने के लिए हेलमेट पहन लिया। एक घर के बाहर खड़ी साइकिल उठाई और पुराने शहर ओर भाग गया। हालांकि क्राइम ब्रांच की मदद से पुलिस ने 5 घंटे बाद उसे दबोचा। आरोपी अभय कोटरा सुल्तानाबाद का रहने वाला है। पहले भी वाहन चोरी में गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी अभय अक्सर पुराने शहर में गांजा खरीदने जाता है। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने उसे दबोचा।

40 हजार गैस उपभोक्ताओं ने नहीं कराई केवायसी

भोपाल। शहर में 40 हजार उपभोक्ताओं ने आखिरी दिन रविवार को रसोई गैस की ई-केवाईसी नहीं कराई। अब उनके कनेक्शन कट सकते हैं। भोपाल के कुल 4.5 लाख गैस उपभोक्ताओं में से 85 प्रतिशत ने ही प्रक्रिया पूरी की है। 40 हजार परिवार अब भी ई-केवाईसी से वंचित हैं। गैस कंपनियों इंडेन, एचपी और भारत गैस ने पहले ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 16 अगस्त तय की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 23 अगस्त किया था। खाद्य विभाग ने आज स्थिति साफ करने की बात कही है।

नहाते समय गहरे पानी में गए, बाहर नहीं निकले भोपाल से परिवार के साथ घूमने गए बुजुर्ग हाथीकुंड में डूबे, मौत

भोपाल। दोपहर मेट्रो
रायसेन जिले के बरुखार गांव के पास स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हाथी कुंड में रविवार शाम नहाते समय भोपाल के 70 वर्षीय बुजुर्ग की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान भोपाल के शाहजहानाबाद निवासी नौशाद खान के रूप में हुई है। ये परिवार के साथ हाथी कुंड घूमने आए थे। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने करीब एक घंटे तक सचिंघ अभियान चलाया। बुजुर्ग का शव पानी से बाहर निकाला गया। बताते हैं, रविवार को परिवार के साथ नौशाद खान हाथी कुंड पहुंचे थे। वे कुंड में

पहले भी हो चुके हादसे
बारिश में हाथी कुंड में जल और पहाड़ों से आने वाले पानी का स्तर बढ़ने पर यहां बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। भोपाल, सुल्तानपुर और मंडीदीप क्षेत्र से युवा और परिवार पिकनिक मनाने आते हैं। लोग नहाते हैं, लेकिन पानी की गहराई की जानकारी न होने से पहले भी यहां कई हादसे हो चुके हैं।

नहाने लगे। नहाते समय अचानक गहरे पानी में चले जाने से वे डूब गए।

मेट्रो एंकर

श्रीवास्तव बोले-‘रिश्ते हिस्सों में बंटते हैं तो हमारे पास किस्से बचते हैं’ ...समय की छटपटाहट और रिश्तों की टीस को स्वर देती हैं मधु शुक्ला

भोपाल। दोपहर मेट्रो
‘रिश्ते हिस्सों में बंटते हैं तो हमारे पास किस्से बचते हैं।’ राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव की यह टिप्पणी डॉ. मधु शुक्ला की रचनाओं के संग्रह ‘कुछ मन के, कुछ मौसम के’ के लोकार्पण समारोह में पुस्तक के मर्म को रेखांकित कर गई। दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में कहा, डॉ. शुक्ला की रचनाएं सिर्फ भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं, बदलते समय और समाज की बेचैनी को भी सामने लाते हैं। उनकी रचनाओं में राम सिर्फ आराध्य नहीं हैं। सांस्कृतिक चेतना जागृत करने वाले प्रतीक हैं। उनकी रचनाओं में परंपरा और आधुनिकता का संवाद है।



समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार प्रो. रामेश्वर शुक्ल ‘पंकज’ ने की। देहरादून से आए वरिष्ठ गीतकार डॉ. बुद्धिनाथ मिश्र मुख्य अतिथि रहे। राज्य सूचना आयुक्त नथी। कार्यक्रम का संचालन घनश्याम मैथिल ‘अमृत’ ने किया। मुख्य अतिथि डॉ.

बुद्धिनाथ मिश्र ने डॉ. मधु शुक्ला के व्यक्तित्व और कृतित्व पर कहा, उन्होंने भोपाल को देश की ‘साहित्यधानी’ बताया। बोले-वे निरंतर सृजन करती रहे। समीक्षक मनोज जैन ‘मधुर’ ने कहा, शुक्ला ने गीतों में समसामयिक मुद्दों को सहज, सरल और स्वाभाविक भाषा में उठाया है।

छबीले हिंडोलना...सिर पर स्वर्ण कलगी में सजे श्रीजी

भोपाल। लखेरापुरा स्थित श्रीजी मंदिर में प्रभु श्रीनाथजी का विशेष श्रृंगार कर छबीले हिंडोलना उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर प्रभु को सिर पर स्वर्ण कलगी, मोती और सोने के आभूषणों से सजाया गया। संध्या काल में कदम की लताओं और फूलों से सजे छबीले कुंज में प्रभु श्रीनाथजी सखियों के साथ मयकी के झूले में विराजमान हुए। रंग-बिरंगे पुष्पों और पतियों से सजाए गए झूले में प्रभु के मनोहारी स्वरूप के श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस अवसर पर प्रभु को मोहनथाल, मटरी और बूंदी के लड्डू का भोग अर्पित किया गया।

प्रदेश के स्कूलों में तीन जन्माष्टमी का पर्व मनाने के निर्देश

भोपाल। प्रदेश के सभी स्कूलों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाना अनिवार्य होगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने इसके आदेश जारी किए हैं। स्कूलों में 1 से 3 सितंबर तक विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे। इस दौरान कृष्ण लीला का मंचन भी होगा। गीता ज्ञान पर नाटक-नृत्य होगा और भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े मिथक तोड़ने को लेकर व्याख्यान होंगे। सांदीपनि स्कूलों में गुरु-शिष्य परंपरा पर आयोजन होगा।

इस साल जन्माष्टमी 4 सितंबर को मनेगी। ऐसे में भगवान श्रीकृष्ण की आराधना करने वाले श्रद्धालु इस दिन व्रत रखकर रात में कान्हा के जन्म के समय पूजा करेंगे। भगवान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला जन्माष्टमी पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में रत रखते हैं और रात में उनके जन्म के समय विशेष पूजा करने के बाद व्रत खेलते हैं।

शहर के 3 अस्पताल किए आयुष्मान से बाहर, लेकिन यह तो 4 साल पहले से ही चल रहा है

अस्पतालों की करतूत..फर्जी मरीज और लूट; मरीज कैसे आयुष्मान भव:

भोपाल। दोपहर मेट्रो
लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए सरकार ने जिस आयुष्मान योजना की शुरुआत की, जिम्मेदारों ने उसी में सेंध लगा दी। राजधानी भोपाल के ऐसे ही तीन अस्पतालों को आयुष्मान योजना से निलंबित कर दिया गया है। इनमें से एक अस्पताल ने तो हद की पार कर दी। अस्पताल ने सरकार से मोटी राशि उगाहने के लिए भोपाल से 650 किमी दूर सिंगरौली व अन्य जिलों से मरीजों को थोक में बुलाकर भर्ती कर लिया।

जांच में 30 मरीजों का रिकॉर्ड खंगाला तो 20 मरीज दूसरे जिलों के मिले। आयुष्मान के सीईओ अरविंद कुमार शाह ने बताया कि यशवी, सूर्याश और मारुति मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल तत्काल प्रभाव से इन अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत नए मरीजों को भर्ती करने पर रोक लगा दी गई है।

यहां योजना के तहत इलाज करा चुके पुराने मरीजों के क्लेम का भी डेस्क ऑडिट किया जाएगा। तीनों ही अस्पतालों को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब तलब किया है। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। इस भ्रष्टाचार की शुरुआत 4 साल पहले 2022 में ही शुरू हो गई थी। तब शहर



चार साल पहले इन पर हुई थी कार्रवाई	
अस्पताल-- जुर्माना राशि	अभी इन अस्पतालों पर पड़ा छापा, थमाए नोटस
■ राजदीप अस्पताल : 32.60 लाख	■ यशवी मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल
■ वीसीएच हास्पिटल : 4.46 लाख	■ सूर्याश स्पेशियलिटी अस्पताल
■ जीवन श्री अस्पताल : 8.63 लाख	■ मारुति स्पेशियलिटी अस्पताल
■ आयुष्मान भारत : 8.26 लाख	■ तीनों अस्पतालों को तत्काल प्रभाव से आयुष्मान योजना में मरीजों को भर्ती करने से रोक लगा दी है।
■ आयुष्मान हास्पिटल : 17.67 लाख	
■ आधार हास्पिटल : 22.90 लाख	
■ किशनानी हास्पिटल : 4.96 लाख	
■ गुरु आशीष हास्पिटल : एकआइआर	

के 8 अस्पतालों की धांधली सामने आई थी। इन अस्सालों ने सामान्य बीमारियों के मरीजों को इलाज के लिए लंबे समय तक भर्ती रखा और धोखाधड़ी की। इनमें से दो अस्पताल पर एकएआईआर भी दर्ज की गई। सवाल है कि 4 साल से

अस्पतालों में लूट होती रही और अब विभाग हरकत में आया। बता दें, सात माह पहले ही आयुष्मान के जीएम और सीईओ के पीए सस्पेंड को सस्पेंड भी कर दिया गया। इसके बाद भी घोटाला चलता रहा।

शाहजहानाबाद स्थित वाजपेयी नगर मल्टी की घटना

पत्नी पर चाकू से किया जानलेवा हमला, मां को बचाने में 12 साल का बेटा भी घायल

भोपाल। दोपहर मेट्रो
शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र स्थित वाजपेयी नगर मल्टी में शनिवार रात दंपती में हुए विवाद के बाद पति ने पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। चाकू का वार गर्दन और कान के पास लगने से महिला को गंभीर चोट आई है। मां को बचाने में 12 साल का बेटा भी चाकू लगने से घायल हो गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। वह भोपाल छोड़कर भागने की फिराक में था।

पुलिस ने बताया, प्रभात कल्याणी (37) पुताई का काम करता है। 21-



22 अगस्त की रात वह घर लौटा तो पत्नी से विवाद होने लगा। विवाद बढ़ने पर उसने चाकू से हमला कर दिया। पत्नी की गर्दन और कनपटी पर चाकू लगने से गंभीर चोट आई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी पति से

लालघाटी से पकड़ाया
वारदात के बाद आरोपी प्रभात फरार हो गया था। पुलिस आरोपी को ढूंढ़ रही थी। इस बीच रविवार को सूचना मिली कि आरोपी शहर से भागने की फिराक में है। उसे लालघाटी से दबोच लिया।

उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। तभी 12 साल का बेटा बीच में आ गया। उसने आरोपी पिता से चाकू छुड़ाने का प्रयास किया। हालांकि इस प्रयास में उसके दोनों हाथों में चाकू लगने से चोट आई है।

रिहायशी क्षेत्र में कमर्शियल एक्टिविटी का मामला

अब निजी अस्पतालों को भी नोटिस, संचालक बोले-बंद करेंगे अस्पताल

भोपाल। दोपहर मेट्रो
रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोपाल नगर निगम नोटस थमा रहा है। इसके पक्ष में रहवासी संघर्ष समिति है तो विरोध में व्यापारी। इन सबके बीच अब नोटिस और कार्रवाई की जद में शहर के स्वास्थ्य संस्थान भी आ गए हैं। अब तक 150 से ज्यादा क्लीनिकों और निजी अस्पतालों को नगर निगम ने नोटिस थमाए हैं।

निजी अस्पताल संचालकों का कहना है कि चिकित्सा संस्थानों की स्थिति सामान्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अलग है। इसे ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया स्पष्ट की जानी चाहिए। इस मुद्दे पर जल्द ही वरिष्ठ पदाधिकारियों के सामने पक्ष रखा जाएगा। सामूहिक आंदोलन की जरूरत पड़ी तो वह भी किया जाएगा। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर अस्पताल बंद रखने जैसे विकल्पों पर भी चर्चा हो सकती है।

शहर में 450 से अधिक नर्सिंग होम तो दो हजार से ज्यादा क्लीनिक चल रहे

शहर में 450 से अधिक नर्सिंग होम और दो हजार से ज्यादा क्लीनिक संचालित हैं। निजी अस्पताल संचालकों का कहना है कि अस्पताल सालाना परिवर्तन शुल्क भी देते हैं। 2005 में मास्टर प्लान में अस्पतालों को परमिसिबल एक्टिविटी के दायरे में रखा गया था, इसलिए कमर्शियल नहीं होते। 2018 में बात आई तो एक नोटिफिकेशन के जरिए अधिभोग परिवर्तन कर शुल्क जमा कराया गया था। सभी अस्पताल यह शुल्क देते हैं। 2018 में अररा कॉलनी में 83 और रोहित नगर में 67 सहित 150 संपत्तियों में अस्पताल, नर्सिंग होम जैसी गतिविधियां संचालित होती मिली थीं।

बैंकों में होल्ड राशि दिलाने में करेंगे मदद

4 जोन के साइबर प्रभारी ठगी पीड़ितों को दिलाएं राहत

भोपाल। दोपहर मेट्रो
साइबर ठगी के मामलों में पीड़ितों की होल्ड राशि समय पर वापस कराने और बिना किसी सलिमता के बैंक खातों पर लगे होल्ड हटवाने के लिए भोपाल पुलिस ने एमआरएम और जीआरएम पोर्टल की निगरानी व्यवस्था मजबूत की है। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल के चार सब-इंस्पेक्टर को शहर के चारों जोन का प्रभारी नियुक्त किया गया है।

उनकी जिम्मेदारी पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग करने, लंबित मामलों का निराकरण कराने और जरूरत पड़ने पर संबंधित थानों की विवेचना में सहयोग करने की होगी। साइबर ठगी के मामलों में ठगी की राशि कई बार विभिन्न बैंक खातों में होल्ड हो जाती है। पीड़ितों को रकम वापस पाने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इसी प्रक्रिया को सरल करने के लिए आइ4सी पोर्टल के तहत एमआरएम व्यवस्था लागू की गई थी। इसके माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के तहत 50 हजार रुपए तक की साइबर ठगी की होल्ड राशि पीड़ित को वापस कराने की कार्रवाई की जाती है।

ठगी की रकम जिस बैंक खाते में पहुंचती है, उस खाते पर भी होल्ड लग जाता है। कई बार खाताधारक का साइबर अपराध से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता और उसका खाता



प्रभारी ऐसे करेंगे काम
शुरुआत में दोनों व्यवस्थाओं में मामलों के लंबित रहने और निगरानी की कमी से पीड़ितों के साथ खाताधारकों को भी परेशानी हो रही थी। अब चारों जोन के लिए अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। प्रभारी सुनिश्चित करेंगे कि होल्ड राशि के पात्र मामलों में कार्रवाई तेजी से हो और 7 दिन में राशि पीड़ित तक पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी कराई जा सके। जांच में किसी सलिमता के प्रमाण नहीं मिलने पर बैंक खातों से होल्ड हटवाने की कार्रवाई की निगरानी भी की जाएगी। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान का कहना है, प्रभारी पेंडिंग मामलों की समीक्षा करकर संबंधित थानों की जांच में सहयोग करेंगे। पीड़ितों की राशि तथा अनावश्यक होल्ड खातों के मामलों का समय पर निराकरण करेंगे।

अनावश्यक रूप से लंबे समय तक होल्ड रहने से परेशानी होती है। ऐसे खातों की जांच और बैंक से होल्ड हटवाने की प्रक्रिया के लिए जीआरएम पोर्टल की व्यवस्था की गई है।

चश्मदीद को लालच-चुप रहो 40 हजार रुपए दूंगा

जुए में विवाद, दो भाइयों ने पीट-पीटकर मार डाला, दोनों गिरफ्तार

भोपाल। दोपहर मेट्रो
पिपलानी थाना क्षेत्र में जुए को लेकर हुए विवाद में घायल युवक की 48 घंटे बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस दोनों आरोपियों रवि और राकेश प्रजापति को गिरफ्तार किया है। 50 क्वार्टर निवासी महेश 20 अगस्त की रात ग्राउंड में कुछ लोगों के साथ जुआ खेल रहा था। जुआ जीतने के बाद वह घर चला गया। इसके बाद रवि ने भाई राकेश के साथ मिलकर उसे फोन कर दोबारा बुलाया। महेश के आते ही दोनों भाइयों ने विवाद शुरू कर दिया और लोहे की रॉड-डंडों से हमला कर दिया।

तभी वहां मौजूद रिश्ते के भतीजे अंशु ने उसे बचाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसे भी नहीं बख्शा और गंभीर घायल कर दिया। मारपीट में महेश के सिर, चेहरे व शरीर पर गंभीर चोटें आईं। दांत भी टूट गए। परिजन उसे एम्स ले गए, जहां शनिवार रात उसकी मौत हो गई।
ताश के पैसे मिलें: एसआई लोकपाल यादव ने बताया कि हमले में घायल भतीजे ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने घटना की गवाही देने पर जान से मारने की धमकी और चुप रहने पर 40 हजार रुपए देने का लालच दिया।

50 विद्यार्थियों का होगा चयन

भोपाल में यूपीएससी की फ्री कोचिंग कराएंगे अफसर; आज से रजिस्ट्रेशन

भोपाल। दोपहर मेट्रो
भोपाल में स्टूडेंट्स को इस बार भी यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) और एमपीपीएससी (मप्र लोक सेवा आयोग) की फ्री कोचिंग दी जाएगी। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। यह अनुभव से निकलकर सामूहिक संवेदना बन जाते हैं। संग्रहालय के अध्यक्ष रामराव वामनकर ने दिया, जबकि आभार नरेंद्र दीपक ने माना।

कोचिंग पॉलीटेक्निक चौराहा स्थित हिंदी भवन में 5 सितंबर से शुरू होगी। एनजीओ से जुड़े रामलखन मीणा ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद सभी वर्गों के विद्यार्थियों के एमपी पीएससी एवं यूपीएससी परीक्षा

की तैयारी कराने के लिए जिला प्रशासन की पहल पर निःशुल्क कोचिंग क्लासेस का नवीन बैच शुरू किया जा रहा है। निःशुल्क कोचिंग क्लासेस की जानकारी के लिए 8357835433, 9584732481 पर संपर्क किया जा सकता है। इस पर रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया भी देखी जा सकती है। जिला प्रशासन भोपाल के मार्गदर्शन में आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा द्वारा निःशुल्क कोचिंग क्लासेस पं. रविशंकर शुक्ल न्यास के सहयोग से संचालित होने जा रही है। इस व्यवस्था से गरीब-जरूरतमंद युवाओं को प्रतियोगी प्रतियोगिताओं की तैयारी करने में आसानी होगी।

त्यो हारों का मौसम आने वाला है और बाजार में मिठास की मांग बढ़ने से पहले ही चीनी न केड़वाहट घोलनी शुरू कर दी है। पिछले पंद्रह दिनों में चीनी के दाम में प्रति किलो करीब 17 रुपये की तेजी केवल घरेलू बजट के लिए चिंता का विषय नहीं, बल्कि देश की खाद्य आपूर्ति व्यवस्था के लिए भी एक गंभीर संकेत है। दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत अगर करीब एक दशक बाद आयात की राह पर लौट रहा है, तो इसे महज बाजार की सामान्य हलचल मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगस्त से नवंबर तक त्योहारों की लंबी

श्रृंखला के कारण चीनी की खपत तेजी से बढ़ती है। मिठाइयों से लेकर घरों की रसोई तक इसकी मांग बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में यदि उत्पादन और उपलब्धता मांग का साथ न दे पाए तो कीमतों का चढ़ना तय है। मौजूदा स्थिति में यही दिखाई दे रहा है। कम उत्पादन, सीमित आपूर्ति और बढ़ती मांग के बीच बाजार का संतुलन डगमगा गया है। इसका सबसे पहला असर आम उपभोक्ता पर पड़ता है, जबकि जमाखोरों और कालाबाजारियों के लिए यही परिस्थिति अवसर बन जाती है। चीनी की बढ़ती कीमतों

कम होती मिठास

की कहानी खेत से बाजार तक जाती है। गन्ने की खेती की लागत लगातार बढ़ी है। सिंचाई, खाद, बिजली, मजदूरी और परिवहन महंगे हुए हैं। दूसरी ओर गन्ने का उत्पादन अनुमान से कम रहने की बात सामने आ रही है। इसके साथ ही गन्ने का एक हिस्सा इथेनॉल उत्पादन की ओर जाने से चीनी के लिए उपलब्ध कच्चे माल पर भी दबाव बढ़ा है। ऊर्जा नीति और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन की जरूरत ऐसे समय अधिक स्पष्ट होकर सामने आती है। नवंबर 2025 में 20 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति को भी कुछ

विशेषज्ञ घरेलू बाजार में आपूर्ति घटने से जोड़ रहे हैं। निर्यात से विदेशी मुद्रा और किसानोंउद्योग को लाभ मिल सकता है, लेकिन घरेलू जरूरतों की कीमत पर लिया गया कोई भी फैसला अंततः उपभोक्ता तक महंगाई बनकर पहुंचता है। नीति की कसौटी यही होनी चाहिए कि उत्पादन अच्छा हो तो निर्यात बढ़े, लेकिन घरेलू बाजार में कमी के संकेत मिलते ही प्राथमिकता बदल जाए। केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देकर तत्काल राहत का रास्ता चुना है।

संसद में सदस्यों की संख्या के साथ पूरे चनावी सिस्टम में सुधार का सवाल

आलोक मेहता

वरिष्ठ पत्रकार



अब इस बात के पूरे आसार दिख रहे हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार संसद में महिलाओं के 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व और सदस्य संख्या लगभग 816 से अधिक करने के संवैधानिक प्रावधान वाले विधेयक आने वाले किसी भी सत्र में पारित करवा लेगी। कांग्रेस और उसके सहयोगियों के विरोध के बावजूद क्षेत्रीय दलों के संसदीय का समर्थन मिलना तय है। लेकिन क्या इससे अधिकाधिक योग्य समाज से जुड़ी ईमानदार महिलाएं और स्वच्छ छवि तथा गंभीर आपराधिक आरोपों से मुक्त सदस्य चुनावों के बल पर संसद में आ सकेंगे? इस तरह का एक सवाल राजनीति में सक्रिय एक सुसंस्कृत परिवार की शिक्षित प्रवक्ता ने पिछले दिनों एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान मुझसे किया।

सचमुच तत्काल इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। इसलिए मैंने अपने इस बार अपने कालम में इस मुद्दे से जुड़ी बातें रखना उचित समझा।

यदि संसद लोकसभा की सीटों का परिसीमन करके संख्या 543 से

बढ़ाकर 816 करती है और महिलाओं के लिए लगभग 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करती है, तो भारतीय लोकतंत्र की चुनावी तस्वीर काफी बदल जाएगी। 816 सीटों के मॉडल में लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसका मतलब है कि नई लोकसभा में कम-से-कम 273 महिलाएँ आरक्षित सीटों के माध्यम से पहुँचेंगी। नई व्यवस्था में लोकसभा का बहुमत भी बदल जाएगा। 543 सदस्यीय वर्तमान लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है, जबकि 816 सदस्य होने पर बहुमत के लिए 409 सांसदों का समर्थन आवश्यक होगा।परिसीमन का दूसरा बड़ा असर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों पर पड़ेगा। अभी लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। नई जनसंख्या-आधारित परिसीमन व्यवस्था में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लगभग 126 से 136 और करीब 70 तक पहुँचने का अनुमान है। अंतिम संख्या परिसीमन आयोग ही तय करेगा।

महिला आरक्षण का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आरक्षित सीटों में भी लगभग एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। करीब 45 करीब 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। इस प्रकार 273 महिला आरक्षित सीटों में अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं का भी संवैधानिक प्रतिनिधित्व रहेगा।परिसीमन का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण पर पड़ेगा। आबादी के आधार पर सीटें बढ़ने से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े और अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर प्रस्तावित मॉडल में उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर लगभग 120 और बिहार की 40 से लगभग 60 हो सकती हैं। महाराष्ट्र लगभग 72, पश्चिम बंगाल 63, तमिलनाडु 59, मध्य प्रदेश लगभग 44 और कर्नाटक लगभग 42 सीटों तक जा सकते हैं। ये अभी संभावित आंकड़े हैं, अंतिम परिसीमन में बदलाव संभव है।वास्तविक संख्या अंतिम रूप से सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव और परिसीमन आयोग की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तय होगी।

दक्षिण भारत की चिंता भी महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है। उनका तर्क है कि यदि केवल वर्तमान आबादी का आधार बनाकर सीटें बाँटी गईं तो जिन राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित की, उनका लोकसभा में सापेक्ष राजनीतिक वजन घट सकता है। दूसरी ओर 816 सीटों का प्रस्तावित मॉडल इस नुकसान को कम करने के लिए कुल सीटों को ही काफी बढ़ाने का रास्ता अपनाता है।इसलिए 816 सीटों का मॉडल केवल महिला आरक्षण का मामला नहीं, बल्कि भारत के संघीय राजनीतिक संतुलन का भी बड़ा प्रश्न है। एक तरफ उत्तर भारत के बड़े राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, दूसरी तरफ दक्षिणी राज्यों को भी मौजूदा सीटों की तुलना में अधिक सीटें मिलेंगी। अंतिम संख्या संसद के कानून और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया से तय होगी।

इसी तरह चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन चुनावी राजनीति के सामने दो गंभीर चुनौतियाँ लगातार बनी हुई हैं—राजनीति का अपराधीकरण और चुनाव में बढ़ता धनबल। पिछले कई दशकों में निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, विधि आयोग और विभिन्न सरकारी समितियों ने इन



समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं। कुछ सुझाव कानून बने, कुछ पर न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले दिए और कई आज भी संसद तथा सरकार के सामने लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने एक फैसले में कुछ महत्वपूर्ण अनिवार्य कही जा सकने वाली सिफारिशें भी की हैं।

सबसे बड़ी समस्या यह है कि केवल आरोप लगने से किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकने की व्यवस्था नहीं है। मौजूदा कानून में मुख्यतः दोषसिद्धि के बाद अयोग्यता होती है। दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को मतदाताओं के सामने अनिवार्य रूप से रखने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। निर्वाचन आयोग ने भी गंभीर आपराधिक मामलों में आरोप तय हो चुके उम्मीदवारों को चुनाव से बाहर रखने का प्रस्ताव दिया है। लेकिन इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए संसद को कानून बनाना होगा।

2013 में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। इसके बाद किसी सांसद या विधायक को ऐसे अपराध में दोषी ठहराया जाता है जिसमें कानून के अनुसार दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है, तो दोषसिद्धि के प्रभाव से सदस्यता समाप्त हो सकती

है। निर्वाचन आयोग ने भी इसे राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार माना गया। लेकिन यहाँ एक बड़ी सीमा है—दोषसिद्धि होने तक मुकदमा चलता रहता है। यदि मामला वर्षों तक लंबित रहे तो केवल आरोप या आरोपपत्र के आधार पर उम्मीदवार स्वतः अयोग्य नहीं होता।2018 में में सुप्रीम कोर्ट ने एक और प्रावधान किया न्यायालय ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे ऐसे उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि सार्वजनिक करें जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। केवल रिकॉर्ड

प्रकाशित करना ही पर्याप्त नहीं माना गया; राजनीतिक दल को यह भी बताना होगा कि उसने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को टिकट क्यों दिया और किसी साफ-सुथरे उम्मीदवार को क्यों नहीं चुना।लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चरण पर भी चुनाव लड़ने पर स्वतः प्रतिबंध नहीं लगाया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्देशों को और मजबूत किया। राजनीतिक दलों को उम्मीदवार चयन के 48 घंटे के भीतर, अथवा नामांकन की पहली तारीख से कम-से-कम दो सप्ताह पहले, आपराधिक मामलों की जानकारी और उम्मीदवार को चुनने का कारण प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया। अभी निर्वाचन आयोग का यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि किसी उम्मीदवार के खिलाफ ऐसे गंभीर अपराध में अदालत द्वारा चार्ज फ्रेम किए जा चुके हों, जिसमें पाँच वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, तो उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था हो।

इसलिए भविष्य का चुनाव सुधार तीन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। न्यायिक निष्पक्षता, मतदाता की पूर्ण जानकारी और गंभीर अपराधों के प्रति शून्य राजनीतिक सहनशीलता। धनबल के मामले में भी यही सिद्धांत लागू होना चाहिए। चुनावी चंदे और खर्च की पूर्ण पारदर्शिता, पार्टी और उम्मीदवार दोनों के खर्च की निगरानी, डिजिटल वित्तीय रिकॉर्ड और सीमित रूप में सरकार द्वारा चुनाव प्रचार अभियान की वित्तीय व्यवस्था मिलकर चुनाव को अधिक समान बना सकते हैं। इस महीने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय में कहा गया है कि चुनावों की आवर्ती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय उम्मीदवारों, मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की शीघ्र सुनवाई और निपटान के लिए न्यायालयों को नामित कर सकते हैं।किसी विशेष चुनाव चक्र में उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमों की वापसी के लिए संबंधित उच्च न्यायालय की मंजूरी आवश्यक है, जो केरल राज्य बनाम के. अजित और अश्विनी कुमार उपाध्याय मामले में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप है।संबंधित न्यायालयों को चुनाव संबंधी लंबित मुकदमों को शीघ्रता से उनके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। निर्वाचन आयोग और संबंधित राज्य सरकारों को 18 नवंबर 2026 को या उससे पहले अनुयायन रिपोर्ट दायित्व करने का निर्देश दिया गया।

अंततः चुनाव सुधार का उद्देश्य केवल अपराधियों को रोकना या खर्च कम करना नहीं है। उद्देश्य यह होना चाहिए कि भारत की संसद और विधानसभाएँ ऐसे प्रतिनिधियों से बनी हो जिनकी राजनीतिक शक्ति का आधार जनता का विश्वास हो—अपराध, भय और बेहिंसाब पैसा नहीं।निर्वाचन आयोग ने अनेक बार सुधारों का रास्ता दिखाया है और सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक सीमाओं के भीतर महत्वपूर्ण रास्ते खोले हैं। अगला निर्णायक कदम संसद और राजनीतिक दलों को उठाना होगा।

—यह लेखक के अपने विचार हैं।

दिनेश मालवीय

वित्तक, रतंभकार



वैसे तो राजनैतिक विमर्शों पर टिप्पणी करना मुझे समय की बर्बादी लगता है, क्योंकि इनमें इतनी गिरावट आ गयी है कि वे टिप्पणी के लायक ही नहीं लगते. बहरहाल, कभी-कभी कोई बात मन को इतना कचोट जाती है कि कुछ कहे बिन रहना अपने कर्तव्य से विमुख होना लगता है। कुछ राजनैतिक लोग अपने सार्वजानिक विमर्शों में 'मनुस्मृति' की घनघोर आलोचना कर रहे हैं। पुणे में एक बड़े नेता ने इस पुस्तक के एक श्लोक के संदर्भ में बताया कि यह स्त्री विरोधी है और स्त्रियों को दासता में रखने का पक्ष लेता है। इसे सही या गलत सिद्ध करने के लिए अनेक तर्क दिए जाते रहे हैं, दिए जा रहे हैं और दिए जाते रहेंगे। लेकिन मैं कुछ अलग बात करना चाहता हूँ।

कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या संसार के किसी भी ग्रंथ में किसी संदर्भ विशेष में कुछ 7सी बातें नहीं कही गई हैं, जो स्पष्ट रूप से स्त्रीत्व के लिए अपमानजनक हैं? जहां तक मैंने पढ़ा-समझा है, ऐसा दावा कोई भी धर्म नहीं कर सकता। बहरहाल, यह भी तथ्य है कि कोई बात किसी संदर्भ में कही गयी हो,लेकिन उसे नासमझ या शरारती लोगोंने सामान्य बनाकर पेश कर दिया हो।

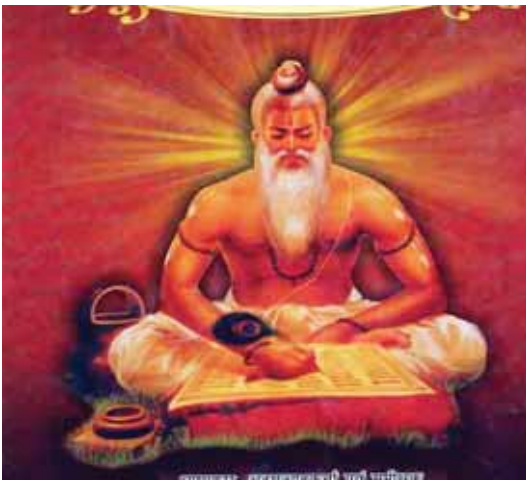
इस संदर्भ में किसी भी धर्म नाम लेने का कोई अर्थ नहीं है। सभी की स्थिति कमोवेश एक जैसी है। किसी धर्म का ग्रंथ कहता है कि स्त्री सारे पापों का मूल है, तो कोई कहता है कि स्त्री में आत्मा ही नहीं होती, कोई इसे बुद्धिहीन मानता है। कोई धर्म स्त्री को मोक्ष का अधिकार नहीं देता तो किसी महापुरुष ने स्त्रियों को दीक्षा के योग्य ही नहीं माना। कोई उसे अपने धर्मस्थलों में जाने की इजाजत नहीं देता तो कोई अपने धर्मस्थलों में उनके लिए अलग सेक्शन रखता है। आज खुद को विकसित कहने वाले देशों में भी स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार बहुत बाद में दिया गया। वहां भी डायन कहकर स्त्रियों को जलाए जाने किए वीभत्स प्रसंग मिलते हैं।

बड़े-बड़े कवि भी स्त्री-निन्दा में पीछे नहीं रहे। यहां भी किसी का नाम लेना उचित नहीं लगता। लेकिन इन कवियों वे भी शामिल हैं, जिन्हें खुद को बहुत प्रगतिशील कहने वाले लोग बहुत बड़ा आदर्श मानते हैं। प्रश्न यह है कि सिर्फ किसी एक ऐसे ग्रंथ को टारगेट करने का उद्देश्य क्या है, जिसकी देश में संविधान लागू होने के बाद कोई प्रासंगिकता नहीं रह गयी है? उसमें जो व्यवस्थाएँ दी गयीं थीं, वे उस समय के अनुरूप उचित रही होंगी, लेकिन आज उनका पालन कौन रहा? यदि इस तरह की आलोचना करनी हो, तो सभी ग्रंथों और पुस्तकों की कीजिए- सिर्फ एक पुस्तक को टारगेट करना आलोचक की मंशा पर सवाल खड़े करता है।

विवेकशील विद्वानों का कहना है कि किसी भी विषय या घटना पर टिप्पणी करने से पहले चार बातों पर विचार किया जाना चाहिए- देश, काल, परिस्थिति और प्रकरण। कोई बात किस जगह कही गयी, जब कही गयी तब समय किस प्रकार

का था, परिस्थितियां क्या थीं और उस बात को कहने का संदर्भ क्या था। लेकिन हो यह रहा है कि किसी एक श्लोक या चौपाई या कविता पर इन चारों तथ्यों पर विचार किए बिना, सिर्फ राजनैतिक लाभ लेने के लिए कुछ भी कह दिया जाता है। यह विवेकहीनता है।

और अगर उपरोक्त ग्रंथ पर नकारात्मक टिप्पणी किसी अन्य समुदाय की खुश करने के लिए की जा रही हैं, तो यह भारतीय समाज के प्रति समझ की कमी है। हमारे देश में हर समाज और समुदाय में अधिकांश लोग इस तरह की बातों को पसंद नहीं करते, खुश होने की तो बात ही छोड़िए। बहरहाल, हर समुदाय में ऐसे कुछ लोग हमेशा से रहे हैं और रहेंगे, जिन्हें ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन व्यापक समाज को सामने रखकर विचार किया जाना चाहिए।



यदि आपके पास देश और समाज के लिए भविष्य की कोई योजना है, तो उसे देश के सामने रखिए, अप्रासंगिक होती जा रही बातों को दोहराने की कोई सार्थकता नहीं है। हर समाज और समुदाय के अधिकांश लोग अपने जीवन के संघर्षों में लगे हैं। बच्चों की परवरिश करनी है, उन्हें पढ़ाना है, उन्हें एक अच्छा और खुशहाल जीवन जीने योग्य बनाना है। उन्हें आप फालतू बातों से कुछ लेना-देना नहीं है, जिन्हें आप इतना महत्व दे रहे हैं। यह स्पष्ट बात दिखाई क्यों नहीं दे रही है। भारतीय समाज सदियों पुरानी सोच से तेजी से बाहर आ रहा है। हर समुदाय के लोग अपनी बेटियों को अपनी हैसियत से बाहर जाकर पढ़ा रहे हैं। लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।

कृपया अपने दायित्व को समझिए। नयी पीढ़ी के लोग वैसे भी अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे। ऐसी निराधार बातें करके क्या आप उनके मन में अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों के प्रति अनास्था पैदा करने का काम नहीं कर रहे।

जब आप 'मनुस्मृति' के उक्त श्लोक के बारे में बता रहे हैं, उन्हें यह भी तो बताइए कि इसी ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि (श्लोक 3.55) 'जिस परिवार में स्त्रियां अपमान या दुःख के कारण दुखी रहती हैं, वह कुल नष्ट हो जाता है, और जिस कुल में वे प्रसन्न रहती हैं, वह हमेशा प्रगति करता है। '

इसी पुस्तक में यह भी लिखा है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। इसी में यह भी लिखा है कि जिस घर के बातों पर विचार किया जाना चाहिए- देश, काल, परिस्थिति और प्रकरण। कोई बात किस जगह कही गयी, जब कही गयी तब समय किस प्रकार

—यह लेखक के अपने विचार हैं।



सुविचार

जिंदगी में सबसे बड़ा धन आपका अच्छा व्यवहार है, क्योंकि यही लोगों के दिलों में आपकी सुंदर पहचान बनाता है।

—अज्ञात



निशाना सच्चे जनवादी उठ



रामकिशोर नाविक

आधी आबादी उठ पाने आजादी उठ रंग बदल ना जाए सोई हुई खादी उठ लोकतंत्र तार तार सच्चे जनवादी उठ शोषित पीड़ित बंदे बक्के प्रतिवादी उठ सोये मत कलमकार दुख के अनुवादी उठ

टेक्नो अपडेट

ईवी चार्जिंग में नई क्रांति, पांच मिनट में सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की सबसे बड़ी चिंता अब बैटरी की क्षमता से ज्यादा चार्जिंग में लगने वाला समय है। इसी चुनौती को खत्म करने के लिए दुनिया की

ऑटो कंपनियाँ ऐसी तकनीक विकसित कर रही हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक कार को पेट्रोल-डीजल वाहन में ईंधन भरने जितने समय में चार्ज किया जा सके। इसी दिशा में चीन की कंपनी ब्रह्मूच ने 2026 में दूसरी पीढ़ी की बैटरी और 1500 किलोवाट क्षमता वाला ब्लस्स। चार्जर पेश किया है। कंपनी का दावा है कि compatible वाहन की बैटरी 10 से 70 फीसदी तक केवल पांच मिनट में चार्ज हो सकती है और नौ मिनट में 97 फीसदी तक पहुंच सकती है। इस तकनीक की खास बात सिर्फ चार्जर की ताकत नहीं, बल्कि बैटरी और चार्जिंग सिस्टम का एक साथ विकसित होना है। नई Blade Battery में ऊर्जा के प्रवाह के लिए हाई-स्पीड चैनल और बेहतर थर्मल मैनेजमेंट दिया गया है। इससे तेज चार्जिंग के दौरान पैदा होने वाली गर्मी को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। कंपनी के मुताबिक नई बैटरी की ऊर्जा घनत्व पहली पीढ़ी की तुलना में पांच फीसदी अधिक है।

1500 किलोवाट का मतलब क्या?: आज सामान्य इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल होने वाले चार्जर की तुलना

में 1500 किलोवाट बेहद बड़ी चार्जिंग क्षमता है। इतनी शक्ति पर चार्जिंग के दौरान बिजली का प्रवाह और गर्मी दोनों बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए केवल शक्तिशाली चार्जर बनाना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हाई-वोल्टेज सिस्टम, बैटरी की बेहतर डिजाइन, प्रभावी कूलिंग और स्मार्ट पावर मैनेजमेंट जरूरी है।

BYD ने चार्जिंग स्टेशन के साथ हाई-कैपेसिटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जोड़ने की भी बात कही है। इसका उद्देश्य चार्जिंग के समय स्थानीय बिजली ग्रिड पर अचानक पड़ने वाले भारी दबाव को कम करना है। इस तकनीक का एक और फायदा सर्द मौसम में दिखाई दे सकता है। कंपनी का दावा है कि माइनस 30 डिग्री सेल्सियस जैसी बेहद ठंडी स्थिति में भी 20 से 97 फीसदी चार्जिंग में कमरे के तापमान की तुलना में केवल तीन मिनट अतिरिक्त लगते हैं। यानी तापमान के कारण तेज चार्जिंग की क्षमता में आने वाली गिरावट को कम करने की कोशिश की गई है।

भारत के लिए क्यों अहम?: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ने के साथ तेज चार्जिंग नेटवर्क की जरूरत भी बढ़ रही है। हाई-पावर चार्जिंग के लिए केवल कार की तकनीक बदलना पर्याप्त नहीं होगा।



पहाड़ी इलाके में जान हथेली पर रखकर दो पाइपों पर चढ़ा दी गाड़ी, देखने वालों की थम गई साँसें

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिन्हें देखकर कुछ सेकंड के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक खतरनाक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक बोलरो पिकअप का ड्राइवर बेहद जोखिम भरे रास्ते पर गाड़ी चलाता दिखाई दे रहा है। वीडियो देखकर जहां कुछ लोग ड्राइवर के हुनर की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई लोग इसे जान जोखिम में डालने वाला कदम बता रहे हैं।

वायरल वीडियो में पहाड़ी इलाके का एक रास्ता नजर आता है, जहां सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे गहरी खाई और पानी बहता हुआ नजर आता है। सामान्य स्थिति में इस रास्ते से किसी वाहन का गुजरना लगभग नामुमकिन लगता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि टूटे हुए हिस्से को पार करने के लिए वहां केवल दो पतली गोल लोहे की पाइप दिखाई देती हैं। यहीं पाइप सड़क के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने का अस्थायी रास्ता बनी हुई हैं। ऐसे में एक सफेद रंग की बोलरो पिकअप को देखकर लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ड्राइवर गाड़ी को बेहद सावधानी से उन दोनों पाइपों पर चढ़ाता है। वीडियो में नजर आता है कि वाहन के पहिए उन्हीं संकरी पाइपों पर टिके हुए हैं।

जिस जगह से वाहन गुजर रहा है, वहां दोनों तरफ गलती की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। गाड़ी थोड़ी सी भी संतुलन खोती तो उसके खाई में गिरने का खतरा था। आसपास खड़े कुछ लोग और मजदूर ड्राइवर को दिशा बताते हुए दिखाई देते हैं। ड्राइवर भी बिना जल्दबाजी किए धीरे-धीरे गाड़ी आगे बढ़ाता है। वह हर मोड़ और हर इंच को बेहद ध्यान से संभालता हुआ नजर

आता है। कुछ क्षणों तक चलने वाली यह पूरी प्रक्रिया देखने वालों के लिए किसी रोमांचक दृश्य से कम नहीं लगती। आखिरकार बोलरो पिकअप उस बेहद संकरे रास्ते को पार कर दूसरी तरफ पहुंच जाती है।

इस वीडियो को एक्स पर @shyamyadavsp95

नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।कुछ लोगों ने ड्राइवर के संतुलन और आत्मविश्वास की जमकर तारीफ की है। कई यूजर्स ने उसे 'खतरों का खिलाड़ी' और शानदार ड्राइवर तक बताया। लोगों का कहना है कि इतनी संकरी जगह पर वाहन को नियंत्रित करना आसान नहीं होता। हालांकि, कुछ यूजर्स ने इस पूरे मामले को बेहद खतरनाक बताया। उनका कहना है कि किसी भी तरह की छोटी गलती ड्राइवर समेत वाहन में मौजूद लोगों की जान खतरे में डाल सकती थी।



जीत का जश्न मनाना पड़ा भारी इंग्लैंड क्रिकेट में फिर नाइटक्लब कांड, गेंदबाज को पुलिस ने लगाई हथकड़ी



नई दिल्ली , एजेंसी

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले एक नए विवाद में फंस गए हैं। डर्बी में एक रात्रि क्लब के बाहर पुलिस ने उन्हें हथकड़ी लगा दी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, कार्स को गिरफ्तार नहीं किया गया और कुछ समय बाद वह टीम के उठरने की जगह लौट गए।

आधी रात को मचा हंगामा

घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है। उस समय कार्स अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के लिए इंग्लैंड की टीम के साथ नहीं थे, बल्कि काउंटी प्रतियोगिता में डरहम की ओर से खेल रहे थे। सामने आए वीडियो में कार्स रात्रि क्लब के बाहर कई पुलिसकर्मियों से घिरे दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने कार्स पर पेय पदार्थ गिरा दिया था। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। क्लब के बाहर पहले से मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभालने के लिए हस्तक्षेप किया और कार्स को कुछ समय के लिए अपने साथ रखा। हालांकि, उनके खिलाफ गिरफ्तारी दर्ज नहीं की गई।

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले बड़ी चिंता- कार्स इंग्लैंड के केंद्रीय अनुबंध वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी से बाहर होने के बावजूद उनके इस मामले ने क्रिकेट बोर्ड का ध्यान खींचा है। बोर्ड ने कहा है कि उसे डर्बी में हुई कथित घटना की जानकारी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद यह तय होगा कि कार्स के खिलाफ किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी या नहीं। मामला क्रिकेट नियामक संस्था तक पहुंचने की भी संभावना है।

जीत के बाद निकले थे जश्न मनाने
घटना से कुछ घंटे पहले कार्स डरहम की ओर से डर्बीशायर के खिलाफ काउंटी मुकाबले में मैदान पर उतरे थे। डरहम ने मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। बेन स्टोक्स ने दूसरी पारी में पांच विकेट झटककर डर्बीशायर की पूरी टीम को सिर्फ 84 रन पर समेट दिया। कार्स ने मुकाबले में दो विकेट हासिल किए। जीत के बाद टीम के कुछ खिलाड़ी डर्बी में जश्न मनाने के लिए बाहर निकले थे। इसी दौरान रात्रि क्लब के बाहर यह पूरा घटनाक्रम हुआ।

पहले भी विवादों में रह चुके हैं कार्स
ब्रायडन कार्स का विवादों से पुराना नाता रहा है। वर्ष 2024 में क्रिकेट नियामक ने उन्हें तीन महीने के लिए निलंबित किया था। जांच में पता चला था कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में 2017 से 2019 के बीच क्रिकेट से जुड़े 303 सट्टे लगाए थे, जो नियमों का उल्लंघन था। इसके अलावा 2023 के कैरेबियाई टोरे के दौरान भी मैदान के बाहर के व्यवहार को लेकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई थी। अब डर्बी की ताजा घटना ने पाकिस्तान के खिलाफ 27 अगस्त से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

मनोरंजन बॉलीवुड का कोना

बेबो ने फूले पेट वाली पोस्ट शेयर कर अफवाहों पर लगाया विराम

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चल रही चर्चाओं के कारण सुर्खियों में हैं। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर उनकी कथित तीसरी प्रेग्नेंसी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। अब करीना ने इन अफवाहों पर ऐसा मजेदार जवाब दिया है, जिसे देखकर उनके प्रशंसक भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

करीना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक मजेदार पोस्ट साझा की। इसमें एक व्यक्ति अपने फूले हुए पेट के साथ पोज देता नजर आ रहा है और पोस्ट पर लिखा है- %दृट ना बे%। करीना ने इसे शेयर करते हुए हंसने वाले और पिज्जा वाले इमोजी लगाए। उनके इस अंदाज से साफ संकेत मिला कि वह अपनी प्रेग्नेंसी की खबरों को गंभीरता से लेने के बजाय मजाक में उड़ा रही हैं।



‘चॉकलेट लाइम जूस’ से दिया खास इशारा

करीना ने इस पोस्ट के साथ फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ का लोकप्रिय गाना ‘चॉकलेट लाइम जूस’ भी जोड़ा। उनके इस अंदाज को सोशल मीडिया यूजरों ने खूब पसंद किया। अभिनेत्री का संदेश साफ था कि पेट के थोड़ा बाहर निकलने का मतलब हर बार प्रेग्नेंसी नहीं होता और इसके पीछे खाने-पीने की वजह भी हो सकती है। करीना से पहले उनकी ननद और सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी भी इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया दे चुकी हैं। उन्होंने करीना की वायरल तस्वीर को लेकर कहा था कि तस्वीर में

पुलिस देखकर भागे होने वाले सास-ससुर दूटा रिश्ता, शादी पर बोलीं कंगना रनौत

बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत और तापसी पन्नू के बीच विवाद गरमाता जा रहा है. एक कार्यक्रम में तापसी पन्नू से कंगना के साथ रिश्ते के बारे में पूछा गया. तापसी ने कहा कि मैंने कंगना से कभी पर्सनल लेवल पर मुलाकात नहीं की, न विवाद से पहले और न बाद में. लोग हमारे बयानों से हमारी परवरिश और बैकग्राउंड का अंदाजा लगा सकते हैं. कंगना ने पलटवार करते हुए तापसी को सस्ती कॉपी बताया और उनकी परवरिश पर भी सवाल उठाए. विवाद के बीच कंगना एक टीवी शो पर पहुंचीं, जहां उनसे शादी को लेकर सवाल किया गया. वहां उनसे पूछा गया कि आपका

शादी को लेकर क्या खयाल है. आप अभिनेता से शादी करेंगी या राजनेता. कंगना ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं इस बारे में क्या कहूँ. शादी को लेकर मेरे बहुत अच्छे खयाल हैं. मैं ऐसा नहीं सोचती कि शादी नहीं होनी चाहिए. या आप इतने पावरफुल हो जाते हैं कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए. कंगना ने कहा कि मुझे लगता है कि हर किसी को एक साथी की जरूरत होती है. मुझे लगता है कि जिस तरह मेरे मम्मी-पापा का रिश्ता रहा है. वो देखकर लगता है कि बच्चे



होने चाहिए. मुझे इतने कोर्ट केसेस आ जाते हैं. जब भी किसी के साथ बात बननी शुरू होती है, पुलिस घर पर आ जाती है. उठ कर ले जाती है. समन आ जाते हैं. एक बार तो होने वाले सास-ससुर मेरे घर पर थे और बाहर समन आ गए. तो वो भाग गए. ये भी उसका एक साइड इफेक्ट है. कंगना ने बेबाक तरीके से बता दिया कि उन्हें शादी से डर नहीं लगता है. वो घर बसाना चाहती हैं, लेकिन कानूनी पचड़े उनका घर नहीं बसने दे रहे. अब देखते हैं कि कंगना को उनका

हॉकी विश्व कप में भारत के सेमीफाइनल का गणित बेहद पेचीदा अर्जेंटीना को हराना होगा, फिर नीदरलैंड्स से आस!

नई दिल्ली , एजेंसी

मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम की सेमीफाइनल की उम्मीदें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के खिलाफ लगातार हार के बाद भी भारत अंतिम-4 की दौड़ में बना हुआ है। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 3-1 से हराकर भारत के लिए उम्मीद की एक खिड़की जरूर खोली है, लेकिन अब भारतीय टीम को इस मौके को भुनाने के लिए सिर्फ जीत नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही उसे नीदरलैंड्स से इंग्लैंड को हराने की उम्मीद भी करनी होगी। पूल-ई में नीदरलैंड्स छह अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। अब दूसरी जगह के लिए भारत, अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच मुकाबला है। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के खाते में तीन-तीन अंक हैं और दोनों का गोल अंतर शून्य है। भारत ने अभी तक कोई अंक हासिल नहीं किया है और उसका गोल अंतर -4 है। ऐसे में टीम इंडिया की स्थिति सबसे मुश्किल है।

भारत की पहली शर्त- अर्जेंटीना को हराना जरूरी

भारत को अपने आखिरी पूल मुकाबले में अर्जेंटीना को हराना ही होगा। अगर यह मैच ड्रॉ रहता है या भारत हार जाता है तो उसकी सेमीफाइनल की उम्मीदें वहीं खत्म हो जाएंगी। लेकिन भारत की जीत के साथ ही एक और नतीजा उसके पक्ष में आना जरूरी है। नीदरलैंड्स को इंग्लैंड को हराना होगा। अगर इंग्लैंड नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत हासिल कर लेता है या

मुकाबला बराबरी पर समाप्त होता है, तो भारत अंतिम-4 की दौड़ से बाहर हो जाएगा। यानी भारत को अपनी जीत के साथ दूसरे मैदान से भी अच्छी खबर का इंतजार करना होगा। भारत के लिए सिर्फ अर्जेंटीना को हराना पर्याप्त नहीं होगा। जीत का अंतर भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। गोल अंतर और किए गए गोलों की संख्या से सेमीफाइनल की तस्वीर बदल सकती है।



टाईब्रेकर में भी भारत की राह आसान नहीं। यहीं भारतीय टीम की चिंता बढ़ जाती है। भारत ने टूर्नामेंट में अब तक सिर्फ एक फील्ड गोल किया है। यह गोल दिलीप्रीत सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ किया था। दूसरी ओर इंग्लैंड के नाम तीन फील्ड गोल हैं और ये तीनों भारत के खिलाफ ही आए थे। ऐसे में अगर स्थिति टाईब्रेकर तक पहुंचती है तो भारत को अतिरिक्त मानदंडों में भी चुनौती मिल सकती है। इसलिए भारतीय टीम की रणनीति साफ होनी चाहिए—अर्जेंटीना के खिलाफ शुरुआत से ही आक्रामक हॉकी खेलते हुए ज्यादा से ज्यादा गोल करना और अपनी जीत का अंतर बढ़ा रखना। जितनी बड़ी जीत भारत हासिल करेगा, उतना ही वह दूसरे मुकाबले के नतीजे और टाईब्रेकर के पेचीदा गणित से बचने की स्थिति में रहेगा।

अर्जेंटीना की चुनौती भी आसान नहीं

हालांकि भारत के सामने सबसे बड़ी बाधा खुद अर्जेंटीना है। दोनों टीमों इस साल एफआईएच प्रो लीग में दो बार आमने-सामने आ चुकी हैं और दोनों मुकाबलों में अर्जेंटीना ने बाजी मारी थी। एक मुकाबले में भारत को 0-8 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, जबकि दूसरे मैच में अर्जेंटीना ने 4-2 से जीत दर्ज की थी। ऐसे में विश्व कप के सबसे अहम मुकाबले में भारत के सामने सिर्फ तीन अंक हासिल करने की चुनौती नहीं है। उसे अर्जेंटीना के खिलाफ अपनी पिछली हार का हिसाब भी चुकाना होगा। सेमीफाइनल का दरवाजा अभी खुला है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भारत को जीत, गोल और नीदरलैंड्स की मदद—तीनों की जरूरत होगी।

आउट होने के बाद सेंड ऑफ से भड़का विवाद यशस्वी पर मंडराया बैन का खतरा! श्रीलंकाई गेंदबाज से भिड़े, आईसीसी के फैसले पर नजर

कोलंबो, एजेंसी

भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो टेस्ट के पहले दिन मैदान पर उस समय तनाव बढ़ गया, जब भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की श्रीलंकाई तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो से तीखी भिड़ंत हो गई। विकेट गंवाने के बाद असिथा ने यशस्वी को आक्रामक अंदाज में सेंड ऑफ दिया। भारतीय बल्लेबाज को यह नागवार गुजरा और देखते ही देखते दोनों खिलाड़ी आमने-सामने आ गए। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच शारीरिक संपर्क भी हुआ। अब इस घटना पर आईसीसी की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। भारत की पहली पारी के 17वें ओवर में यह पूरा घटनाक्रम हुआ। यशस्वी ने असिथा फर्नांडो के इसी ओवर में लगातार तीन चौके जड़कर श्रीलंकाई गेंदबाज पर दबाव बनाया था। लेकिन आखिरी गेंद पर असिथा ने जोरदार वापसी की। अंदर आती गेंद यशस्वी के बल्ले का किनारा लेकर सीधे स्टंप्स से जा टकराई और उनकी पारी खत्म हो गई।

विकेट लेने के बाद असिथा ने जोरदार अंदाज में जश्न मनाया और यशस्वी को सेंड ऑफ दिया। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। मामला तब और गरमा गया, जब यशस्वी पवेलियन की ओर जाने के बजाय असिथा की तरफ बढ़ गए। यशस्वी को शांत करने के लिए देवदत्त पंडिक्रूल ने उन्हें वहां से ले जाने की कोशिश की। श्रीलंका के अन्य खिलाड़ी भी मौके पर पहुंच गए। लेकिन दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे के बेहद करीब आ गए। इसी दौरान उनके सिर आसपस में टकराते हुए दिखाई दिए। यही शारीरिक संपर्क अब पूरे मामले को गंभीर बना रहा है।मैच अधिकारियों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसे महज मैदान पर हुई मार्गमर्मी माना जाए या जानबूझकर किया गया शारीरिक संपर्क। अगर मामला दूसरे स्तर का माना गया तो यशस्वी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।



क्या एक टेस्ट से बाहर हो सकते हैं यशस्वी?

आईसीसी के आचार संहिता में मैदान पर शारीरिक आक्रामकता और हिंसक व्यवहार के लिए सख्त प्रावधान हैं। संबंधित धाराओं के तहत खिलाड़ी पर जुर्माना, डिमिरेट अंक और गंभीर स्थिति में निलंबन तक लगाया जा सकता है। यशस्वी के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि पिछले 24 महीनों में उनके खाते में कोई डिमिरेट अंक नहीं है। लेकिन अगर इस मामले में उन्हें कम से कम चार डिमिरेट अंक मिलते हैं, तो वह एक निलंबन अंक में बदल सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें एक टेस्ट या दो वनडे/दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए प्रतिबंध डोलाया पड़ सकता है।

लेवल-2 में पहुंचा मामला तो बढ़ेगी मुश्किल

आईसीसी अनुशासनात्मक मामलों को अलग-अलग स्तरों पर देखता है। लेवल-1 में आमतौर पर एक या दो डिमिरेट अंक मिल सकते हैं, जबकि लेवल-2 में तीन या चार अंक तक की सजा हो सकती है। अगर इस घटना को कम से कम लेवल-2 का उल्लंघन माना जाता है, तो यशस्वी पर एक टेस्ट मैच का प्रतिबंध लगने की संभावना बन सकती है। लेवल-3 और लेवल-4 में मामला पहुंचने पर सजा और भी कड़ी हो सकती है। लेवल-4 सबसे गंभीर श्रेणी है, जिसमें लंबे प्रतिबंध से लेकर आजीवन प्रतिबंध तक का प्रावधान है। हालांकि मौजूदा घटना को उस स्तर तक पहुंचना अभी तय नहीं है। यशस्वी के करियर में यह पहला ऐसा विवाद नहीं है। 2022 के दलीप ट्रॉफी फाइनल में वेस्ट जोन की ओर से खेलते हुए उनकी साइथ जोन के टी रवि तेजा के साथ कई बार नोकझोंक हुई थी।



मेट्रो बाजार

नई दिल्ली। भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील सैद्धांतिक रूप से करीब पूरी हो गई है और अब दोनों पक्ष कानूनी और तकनीकी भाषा पर कार्य कर रहे हैं। यह जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दी।

राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम में गोर ने कहा कि समझौते की मुख्य बातें तय हो गई थीं और बाकी काम में टेक्स्ट के कुछ हिस्सों को फिर से

भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील करीब पूरी, कानूनी और तकनीकी भाषा पर काम जारी

व्यवस्थित और अंतिम रूप देना शामिल था। गोर ने कहा, «सिद्धांत रूप में, ट्रेड डील का लगभग सारा काम पूरा हो चुका है। उन्होंने समझौते को अंतिम रूप देने में हुई देरी का मुख्य कारण कानूनी और तकनीकी भाषा से जुड़ी प्रक्रियाओं को बताया। अमेरिकी राजदूत ने अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्तावित उस कानून को लेकर जताई जा रही चिंताओं पर भी बात की, जिसके तहत रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि इस कदम को

राजनीतिक दलों के दोनों पक्षों के नेताओं का समर्थन मिल रहा है और इस बात पर जोर दिया कि यह ब्रह्मट हाउस की तरफ से शुरू की गई पहल नहीं है। गोर ने कहा, «यह ऐसी चीज नहीं है जिसका ब्रह्मट हाउस ने समर्थन किया है। आपको राष्ट्रपति ट्रंप का इसे आगे बढ़ाते हुए कोई क्लिप नहीं मिलेगा।» यह मानते हुए कि इस कदम का भारत पर असर पड़ सकता है, उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस-यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं।

देश की शीर्ष 10 में से चार कंपनियों का मार्केटकैप 87,000 करोड़ से अधिक घटा

मुंबई। देश की शीर्ष 10 में से चार कंपनियों का मार्केटकैप बीते हफ्ते 87,960.29 करोड़ रुपए घट गया है। इसकी वजह भारतीय शेयर बाजार में व्यापक आधार पर बिकवाली थी। इस दौरान संसेक्स में 468.42 अंक या 0.60

17-21 अगस्त के कारोबारी सत्र में भारती एयरटेल का मार्केटकैप 28,052.96 करोड़ घटकर 12,14,963.15 करोड़ रुपए हो गया है। टीसीएस का बाजार मूल्यंकन 22,070.34 करोड़ घटकर 8,31,436.51 करोड़,



प्रतिशत गिरावट के साथ 77,540.83 और निफ्टी में 114 अंक या 0.47 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,252 पर था। जिन कंपनियों के मार्केटकैप में कमी आई है, उनमें भारती एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) का नाम शामिल हैं।दूसरी तरफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी), रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलएंडटी, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक के मार्केटकैप में कमी देखी गई।

एसबीआई का मार्केटकैप 20,861.20 करोड़ रुपए घटकर 9,64,968.76 करोड़ और हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार मूल्यंकन 16,975.79 करोड़ कम होकर 4,73,912.56 करोड़ हो गया है। वहीं, एलआईसी का मार्केटकैप 12,650 करोड़ बढ़कर 5,35,980.31 करोड़ रुपए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केटकैप 8,119.53 करोड़ बढ़कर 17,78,175.59 करोड़ रुपए, एलएंडटी का बाजार मूल्यंकन 3,487.83 करोड़ बढ़कर 5,62,460.94 करोड़ और बजाज फाइनेंस का मार्केटकैप 3,424.28 करोड़ बढ़कर 6,80,621.62 करोड़ हो गया है।



हिंदुकुश हिमालय में तेजी से पिघलती बर्फ और सिकुड़ते हिमनद दक्षिण एशिया के लिए गंभीर चेतावनी बन गए हैं। इस क्षेत्र पर बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिखाई दे रहा है। इसिमोड के अनुसार, वर्ष 2000 के बाद हिमनदों में बर्फ के नुकसान की रफ्तार दोगुनी हुई है, जबकि 2026 में बर्फ का आवरण दीर्घकालिक औसत से 27.8 प्रतिशत कम रहा। इसका असर नदियों, कृषि, पेयजल और जलविद्युत पर पड़ सकता है। साथ ही अचानक बाढ़, भूस्खलन और हिमनदीय झीलों से जुड़ी आपदाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अनियोजित निर्माण और पर्यटन का दबाव हिमालय की संवेदनशील पारिस्थितिकी को और कमजोर कर रहा है। वैज्ञानिक निगरानी, जल संरक्षण और प्रकृति के अनुकूल विकास ही इस संकट से निपटने का रास्ता हैं।

उपजाऊ जमीन और पर्यावरण बचाने के लिए लिया फैसला, डीएमके ने सरकार को घेरा परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द, सीएम विजय बोले- ‘मैं प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा हूं’

चेन्नई, एजेंसी
तमिलनाडु में चेन्नई के पास प्रस्तावित परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना को भारी विरोध के बाद सरकार ने रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने घोषणा की कि सरकार परंदूर में नया हवाई अड्डा बनाने से जुड़े सभी कदम वापस ले रही है। उन्होंने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन किसानों के कल्याण की कीमत पर नहीं। मुख्यमंत्री ने परियोजना के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे किसानों और स्थानीय लोगों के साथ खड़े होने की बात कही। चेन्नई से करीब 70 किलोमीटर दूर कांचीपुरम जिले के परंदूर में प्रस्तावित इस एयरपोर्ट का स्थानीय स्तर पर लंबे समय से विरोध हो रहा था। प्रदर्शनकारियों ने बहुफलसी उपजाऊ कृषि भूमि के नुकसान और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंता जताई थी। टीवीके भी शुरुआत से इस आंदोलन के समर्थन में रही है। सरकार के फैसले के बाद डीएमके और सत्तारूढ़ टीवीके के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ गया है। डीएमके नेता दुर्ईमुरुगन ने सरकार से पिछली परियोजना से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है।

डीएमके ने फाइलें सार्वजनिक करने की मांग की



किसानों के समर्थन में विजय का फैसला

परंदूर एयरपोर्ट परियोजना को रद्द करने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कहा कि सरकार जनता से किया वादा पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे औद्योगिक विकास के लिए जरूरी हैं, लेकिन विकास किसानों के हितों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री के मुताबिक, परियोजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे स्थानीय लोगों और किसानों के साथ वह मजबूती से खड़े हैं। परंदूर में एयरपोर्ट के लिए बड़ी मात्रा में कृषि भूमि के इस्तेमाल का विरोध किया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों ने बहुफलसी जमीन, जलाशयों और पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान को लेकर सवाल उठाए थे। टीवीके ने भी इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन दिया था।

अब नए टिकाने की तलाश

परंदूर से बदलेगा प्लान
तमिलनाडु सरकार ने परंदूर परियोजना रद्द करने के साथ चेन्नई के लिए नए एयरपोर्ट स्थल की तलाश जारी रखने के संकेत दिए हैं। सत्ता में आने के बाद से ही विजय सरकार ने प्रस्तावित स्थल की समीक्षा की बात कही थी। टीवीके नेताओं का कहना था कि स्थानीय जलाशयों और उपजाऊ कृषि भूमि की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक स्थानों पर विचार किया जा रहा है। परंदूर परियोजना को लेकर केंद्र सरकार भी पहले कदम बढ़ा चुकी थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अप्रैल 2025 में कांचीपुरम जिले में एयरपोर्ट निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। अब परियोजना रद्द होने के बाद चेन्नई की बढ़ती हवाई जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार को नया स्थान और नई योजना तैयार करनी होगी।

फर्जी चालानों से करोड़ों की कर चोरी पर ईडी का शिकंजा, 9 ठिकानों पर छापेमारी

लखनऊ, एजेंसी
फर्जी चालान और कथित कर चोरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार तड़के उत्तर प्रदेश और हरियाणा में एक साथ नौ ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और फरीदाबाद में हुई यह कार्रवाई धन शोधन निवारण कानून के तहत जम्बूद्वीप एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े मामले में की जा रही है। जांच अधिकारियों के मुताबिक, कथित तौर पर बिना वास्तविक माल की आवाजाही के फर्जी चालान और परिवहन



दस्तावेज तैयार किए गए। इन्हीं के आधार पर कर लाभ हासिल करने और उसे दूसरी इकाइयों तक पहुंचाने का आरोप है। तलाशी के दौरान कारोबारी दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और लेनदेन से जुड़े कागजात खंगाले जा रहे हैं। जांच में करीब 9.63 करोड़ रुपये का कर लाभ कथित तौर पर गलत तरीके से हासिल किए जाने और 10.28

करोड़ का लाभ दूसरी इकाइयों तक पहुंचाए जाने की बात सामने आई है। अधिकारियों को शक है कि कई कागजी कंपनियों के जरिए रकम अलग-अलग खातों में घुमाई गई। अब श्रद्ध धन के पूरे प्रवाह और वास्तविक लाभार्थियों का पता लगाने में जुटी है। कथित कर लाभ के इस नेटवर्क में कई ऐसी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया, जिनकी भूमिका मुख्य रूप से कागजी लेनदेन तक सीमित होने का संदेह है। इन कंपनियों के जरिए रकम को कई चरणों में अलग-अलग बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाने की बात सामने आई है।

फर्जी इंस्टा आईडी से महिला को तंग कर रहा था सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नई दिल्ली, एजेंसी
हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से महिला को परेशान किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पहचान छिपाकर इंस्टाग्राम पर एक महिला के खिलाफ भड़काऊ, मानहानिकारक और यौन रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की थीं। साइबर क्राइम पुलिस ने आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल जब्त किया है। पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर उसे ट्रैक कर गिरफ्तार किया है। आरोपी ने महिला की छवि खराब करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक कमेंट पोस्ट किया था। इंजीनियर पर फर्जी इंस्टा अकाउंट बना राजनीतिक रूप से प्रभावशाली महिला के खिलाफ अभद्र, मानहानिकारक टिप्पणी पोस्ट करने का आरोप है।

मेट्रो एंकर गन्ने की खेती से दूर हो रहे किसान, उत्पादन में 7.74 फीसदी गिरावट पंजाब में गन्ने की मिठास घटी, 6 साल में 69.1 लाख टन पर पहुंचा उत्पादन

चंडीगढ़, एजेंसी
पंजाब में गन्ने की पैदावार लगातार घटने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। गन्ना विकास निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले छह वर्षों में औसतन 7.74 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 में 74.9 लाख टन उत्पादन था, जो 2025-26 में घटकर पिछले वर्षों के सबसे निचले स्तर 69.1 लाख टन पर पहुंच गया। गन्ने का रकबा घटने के साथ चीनी की कीमतों में भी उछाल देखा जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, किसानों को भुगतान में देरी, बढ़ती लागत और कटाई के लिए मजदूरों की कमी के कारण किसान गन्ने से दूरी बना रहे हैं। सरकार उन्नत बीज, सब्सिडी वाली मशीनरी और प्रशिक्षण के जरिए खेती को बढ़ावा देने का प्रयास



कर रही है। वहीं, चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने बाजार में स्टॉक और आपूर्ति की निगरानी भी सख्त कर दी है।

जमाखोरी पर सरकार का पहरा

चीनी की बढ़ती कीमतों और संभावित जमाखोरी को देखते हुए पंजाब सरकार ने स्टॉक

भुगतान में देरी और बढ़ती लागत बनी बड़ी वजह

पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं कृषि विशेषज्ञ विनोद कुमार चौधरी के अनुसार, गन्ने की खेती से किसानों के दूर होने का सबसे बड़ा कारण फसल का भुगतान समय पर नहीं मिलना है। इसके अलावा कटाई के लिए मजदूरों की भारी कमी और खेती की बढ़ती लागत ने भी किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में कई किसान गन्ने के बजाय गेहूं और धान जैसी पारंपरिक फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के साथ उत्पादन लागत कम करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। गन्ने की खेती में गिरावट फसल विविधीकरण की योजनाओं के लिए भी चुनौती है। साथ ही, पंजाब में पहले से घटते भूजल स्तर के बीच टिकाऊ कृषि नीति की जरूरत और अधिक बढ़ गई है।

और बाजार में आपूर्ति की निगरानी सख्त कर दी है। नई व्यवस्था के तहत कोई भी चीनी कारोबारी एक स्थान पर 4,000 किंवटन से अधिक स्टॉक नहीं रख सकेगा। खरीदी गई चीनी को 30 दिन से अधिक समय तक रखने पर भी रोक लगाई गई है। यह व्यवस्था 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। खाद्य एवं

नागरिक आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारूचक ने विभागीय अधिकारियों को चीनी की उपलब्धता और बाजार आपूर्ति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाकर आम उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है।

बराड़ का कबूलनामा-ड्रग तरकरी के कारण हरदीप निज्जर को मारा

नई दिल्ली, एजेंसी
खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। खालिस्तान समर्थक आतंकवादी परमजीत सिंह पम्मा के साथ बातचीत के एक लोक ऑडियो में, गैंगस्टर गोल्डी बरार ने जून 2023 में कनाडा में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रचने की बात कबूली है। बराड़ ने कहा- निज्जर, को ड्रग तरकरी व नशीली दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने में शामिल होने के कारण निशाना बनाया गया था। खुफिया सूत्रों ने पुष्टि की है, ऑडियो में आवाज बराड़ की ही थी। भारत में कई

हत्याओं, जिनमें गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी शामिल है, के लिए वांछित बराड़ को यह कहते सुना जा सकता है कि निज्जर द्वारा किशोरों के बीच ड्रग्स को बढ़ावा देने से वह नाराज था। यह बात 'ऑपरेशन हार्डबॉल' के दौरान सामने आई, जो अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट के खिलाफ अमेरिका और कनाडा की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान था। जांच में बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई को निज्जर की हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था। इससे हाई-प्रोफाइल हत्या को राज्य-प्रायोजित हत्या के बजाय गैंगवार से जुड़ी हत्या माना गया।